tion grants loans to eligible members of Backward Classes for a variety of viable economic activities broadly categorised under the following groups: —

(i) Agricultural and allied fields such as animal breeding, poultry fanning, bee keepinnig and also for purchase of equipments for agricultural services.

(ii) Artisan and traditional occupations like barbers, washermen, tailors weavers, carpenters, potters, blacksmiths, masons, malies etc.

(iii) Self employment in technical tradeg such as electrician, plumber motor and refrigeration mechanics, T.V., radio repair etc.

(iv) Small business like tea shops, provision, book shops, photocopier services, newspaper-vendors etc.

(v) Small scale and tiny industry.

(vi) Transport services like auto-rickshiaws, cycle rickshaws, tempos and animai driven carts Trucks Mini buses and light commercial vehicles are considered preferably for groups of beneficiaries.

The above list is illustrative and not exhaustive.

(c) Loans of Rs. 224 crores have been sanctioned for 2.56 lakh ■beneficiaries in tenms of self and wage employment upto 28.2.1995. Out of this sanctioned amount Rs. 107.65 crores has been disbursed to the state channelising agencies upto 28.3.1995.

पहाड़ी कोरबा और बिरहोर जनजातियों को सहायता

3021. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी कोरबा तथा बिरहोर जनजातियों के अस्तित्व को बचाने और उनका विकास करने हेतु किन-किन राज्यों को सहायता प्रदान की गई हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है और इन जनजातियों की राज्य-वार जनसंख्या कितनी-है ;

(ख) इन जनजातियों के विकास में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं और क्या इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु किए जा रहे कार्यों और तैयार की जा रही योजनाओं की समीक्षा हेतु अनुसंधान कार्य करने के लिए कोई केन्द्रीय दल इन राज्यों में भेजे गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भेजे गए केन्द्रीय दलों और उनके प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) मध्य प्रदेश में इन दोनों जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए गठित एजेंसी के माध्यम से कितनी धनराशि व्यय की गई हैं और उक्त वर्षों के दौरान राज्य के अन्य विभागों ने कितनी धनराशि व्यय की है ; और

(ङ) उनकी उपलब्धियों का वास्तविक ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पहाड़ी कोरबा नामक किसी अनुसूचित जनजाति को आदिवासी के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। तथापि अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचित सूची में कोरबा जनजाति का निम्नलिखित तरीके से उल्लेख है :—

कोरबा	बिहार, पश्चिम
कोदाक सहित	बंगाल मध्य
कोरबा	प्रदेश

बिरहोरा को निम्नलिखित प्रकार से अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है :

बिरहोरा---बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल

बिरहूल---मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र

बिरहोर

1981 की जनगणना के अनुसार कोरवा तथा बिरहोरा की जनसंख्या विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) :

उन राज्यों के नामों के बारे में सूचना जिन्हें उपरोक्त नामों की विद्यमान दो अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षोपायों के लिए सहायता प्रदान की गई तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान नधाराशि प्रदान की गई है, एकत्र की गई है, एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन राज्यों में इन अनुसूचित जनजातियों के संबंध में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए अनुसंधान क्रियाकलाप चलाने हेतु कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है।

(इन अनुसूचित जनजातियों के) विकास के मार्ग में अड़चनों तथा इन अड़चनों को दूर करने संबंधी योजना के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार कोरवा तथा बिरहोरा की जनसंख्या निम्नलिखित है :---

कोरवा	बिहार	21940
कोरवा	पश्चिमी बंगाल	2493
कोरवा कोदक	मध्य प्रदेश	15340
बिरहोरा	पश्चिमी बंगाल	658
बिरहोरा	बिहार	4377
बिरहोरा	उड़ीसा	142
बिरहूल, बिरहोर	मध्य प्रदेश	561
बिरहूल, बिरहोर	महाराष्ट्र	212

पिछड़े वर्गों का प्रतिशत

3022. **श्री ईश दत्त यादव:** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है ; और

(ख) सरकार ने पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक-स्थिति सुधारने हेतु क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की प्रतिशतता के संबंध में जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं